University of Lucknow | Centenary Year
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी वर्ष

University in News on 08 June 2021

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

कम्प्यूटर और होम साइंस पीएचडी प्रवेश मेरिट जारी

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लगभग दो साल से प्रवेश के लिए भटक रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 के कम्प्यूटर साइंस एवं होम साइंस के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। विश्विद्यालय प्रशासन ने लंबी कवायद के बाद इन विषयों में पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी है।

निदेशक प्रवेश के अनुसार विषयों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर पूरी मेरिट सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि 08 जून को सत्र 2019-20 के पीएचडी कम्प्यूटर साइंस एवं होम साइंस विषयों में खाली सीटों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए चार दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद वे कोई दावा नहीं कर सकेंगे। उक्त विषयों में प्रवेश परीक्षा के बाद डीआरसी आदि को लेकर कुछ दिक्कत फंस गई, जिसकी वजह से अन्य विषयों में तो प्रवेश हो गए, लेकिन इनमें नहीं हो सके।

सत्र 2019-20 के पीएचडी प्रवेश का मामला

आज जारी होगी प्रवेश के पात्र अभ्यर्थियों की सूची

इतना ही नहीं जब सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश आवेदन जारी हुए तो कम्प्यूटर साइंस में सीट भी जारी कर दी गई। 'अमर उजाला' ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और 05 अप्रैल को 'पिछले साल के प्रवेश हुए नहीं और नई सीटें निर्धारित' शीर्षक से खबर प्रकाशित की। जिसका विवि प्रशासन ने संज्ञान लिया और इन दोनों विभागों की डीआरसी आदि की दिक्कतें दूर कर ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित किया। अब इसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके नए सत्र में प्रवेश दिए जाएंगे।

कॉलेजों के यूजी शिक्षकों को शोध का अवसर देने पर मंथन

माई सिटी रिपोर्टर

डीन एकेडमिक्स ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कमेटी के साथ की बैठक

शोध की गुणवत्ता के साथ कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी विचार

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने 524 सहयुक्त महाविद्यालयों के स्नातक के शिक्षकों को शोध का अवसर देने पर मंथन शुरू कर दिया है। इस क्रम में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के निर्देशानुसार सोमवार को विवि के सभी विभागाध्यक्ष, डीन, डीआरसी चेयरपर्सन की एक बैठक डीन एकेडमिक्स प्रो. राकेश चंद्रा की अध्यक्षता में गठित कमेटी के साथ हुई।

बैठक में प्रो. पूनम टंडन ने कहा की विवि के पास ऐसे कई शिक्षकों के आवेदन आए हैं, जो शोध कराना चाहते हैं और करना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे सभी अध्यापकों के शोध कैरिअर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विवि निर्णय लेंगे। कई शिक्षकों ने महाविद्यालयों के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान आकर्षित किया।

यह भी आशंका जताई गई कि यदि सभी महाविद्यालयों को पीएचडी कराने का अवसर दिया जाता है तो क्या इतनी बड़ी संख्या छात्रों को विवि एक साथ कोर्स वर्क करा पाएगा। शिक्षकों ने विश्वास जताया कि इसके लिए महाविद्यालय भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे।

बैठक में लविवि की डीएसडब्ल्यू प्रो. पूनम टंडन, डॉ. संगीता साहू, प्रधानाचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोतर महाविद्यालय डॉ. अनुराधा तिवारी और प्रधानाचार्य, डीएवी डिग्री कॉलेज डॉ. अंजनी मिश्रा भी उपस्थिति थे। इसी क्रम में मंगलवार को विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य के साथ बैठक होगी। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआकटा) अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय व महामंत्री डॉ. अंशु केडिया ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए कमेटी के गठन के निर्णय का स्वागत किया है।

NBT PAGE 4

एलयू में हैं पक्षियों की 65 प्रजातियां, 100 वर्ष पुराने वृक्ष भी हैं संरक्षित

■ **एनबीटी, लखनऊ:** ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट को लखनऊ विश्वविद्यालय बड़ी उपलब्धि मान रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसर में एक हजार किलोवाट के सोलर पैनल लगवाकर विवि प्रति माह पांच लाख रुपये यानी वर्ष में करीब साठ लाख रुपये बचा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार विवि परिसर में पक्षियों की 65 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें हॉर्नबिल, ट्री पाई, उल्लू, वारबेट, सनबर्ड और रॉबिन शामिल हैं। परिसर में तितलियों की लगभग 25 प्रजातियां भी पाई गई हैं।

जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. सुधीर कुमार मुतावेक वनस्पतियों और जीवों के मामले में विश्वविद्यालय वेहद समृद्ध है। अब हमारे पास ग्रीन ऑडिट के रूप में रेकॉर्ड भी है। ऑडिट में यह भी पाया गया कि लविवि अपने परिसर में 100 साल से अधिक पुराने पेड़ों को संरक्षित किए है। इतना ही नहीं पानी की गुणवत्ता जांचने और अपशिष्ट प्रवंधन व जल पुनर्चक्रण की तैयारी भी चल रही है। दावा है कि ऑडिट रिपोर्ट से नैशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क और नैशनल असेसमेंट ऐंड एक्रेडिटेशन काउंसिल में वेहतर स्थान हासिल करने में मदद मिलेगी।

ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट : सोलर पैनल से एलयू बचा रहा प्रति वर्ष ₹60 लाख

40 से अधिक प्रकार के पेड़

विवि की प्रो. अमिता कनौजिया के अनुसार परिसर में 40 किस्मों के सौ से अधिक पेड़ों के साथ तमाम वनस्पतियों के पौधे हैं। परिसर में चंदन, पारिजात, सफेद सिरी, चीर, रवड़, चिनवेरी, ताड़, अशोक, पलाश और खिरनी आदि प्रजाति के वृक्ष लगे हैं।

PIONEER PAGE 3

महाविद्यालयों में शोध को लेकर कमेटी ने एलयू के डीन व एचओडी संग की बैठक

आज महाविद्यालयों के प्राचार्यों संग होगी बैठक

लखनऊ। महाविद्यालयों में शोध की संभावनाओं की तलाश के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय की तरफ से गठित पांच सदस्यीय टीम ने सोमवार को विवि के डीन व एचओडी के साथ बैठक कर चर्चा की। कमेटी मंगलवार को महाविद्यालयों के साथ बैठक कर शोध के संभावनाओं की समीक्षा करेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के निर्देश पर आज विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, डीआरसी के चेयरपर्सन एवं समस्त संकाय अध्यक्षों की एक बैठक डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर राकेश चंद्रा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर पूनम टंडन, व्यापार प्रशासन विभाग से डॉ संगीता साहू, प्रधानाचार्य, नेताजी सुभाष राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीगंज डॉ अनुराधा तिवारी, और प्रधानाचार्य, डीएवी डिग्री कॉलेज ऐशबाग डॉ अंजनी मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर राकेश चंद्रा ने सभी के साथ एजेंडा सांझा किया और सभी उपस्थित वरिष्ठ अध्यापकों से अपने विचार सबके समक्ष रखने के लिए आग्रह किया। प्रोफेसर पूनम टंडन ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा की विश्वविद्यालय के पास ऐसे कई अध्यापकों के आवेदन आए हैं जो शोध कराना चाहते हैं और करना चाहते हैं।

i-NEXT PAGE 4

लर्निंग सिस्टम में शामिल होंगे कॉलेज

लखनऊ विश्वविद्यालय के आनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग अब कालेज और दूसरे विश्वविद्यालय भी कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराना होगा. नामांकन करने वाले संस्थानों को विश्वविद्यालय प्रशिक्षण देगा, साथ ही उन्हें बैकअप भी प्रदान करेगा. विश्वविद्यालय ने महामारी के शुरुआत में छात्र हित में आनलाइन शिक्षण के लिए व्यावसायिक आनलाइन प्लेटफार्म का परीक्षण किया था. प्रवक्ता डा. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित इन-हाउस कापीराइट डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रैटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फार ट्रांसफार्मेटिव एजुकेशन (स्लेट) दो से अधिक शैक्षणिक सत्रों से चल रहा है. यह छात्रों और शिक्षकों की जरूरतों के अनुरूप है. छात्र मूल्यांकन, टाइम टेबल मैनेजमेंट, छात्र उपस्थिति की निगरानी, फाइलों का आदान-प्रदान सहित तमाम सुविधाएं हैं, इसलिए कोई भी शिक्षण संस्थान इसमें मामूली शुल्क के आधार पर नामांकन कर इसका प्रयोग कर सकता है.

HINDUSTAN PAGE 6

पीएचडी का कोर्स वर्क पूरा हो पाने पर शिक्षकों को संशय

बैठक

लखनऊ | कार्यालय संवाददाता

लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध का दायरा बढ़ाने एवं नई शिक्षा नीति के शोध को बढ़ावा दिए जाने को लेकर सोमवार को ऑनलाइन बैठक की गई। जिसमें यह आशंका भी सामने आई कि यदि सभी महाविद्यालयों को इतनी अधिक मात्रा में पीएचडी कराने का अवसर दे दिया गया तो इतने अधिक छात्रों का कोर्स वर्क पूरा कराने को लेकर क्या विश्वविद्यालय व्यवस्था कर पाएगा।

डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर राकेश चंद्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, डीआरसी के चेयरपर्सन एवं समस्त संकाय अध्यक्ष शामिल रहे। समिति के सदस्य-शिक्षकों ने कहा कि महाविद्यालयों को यदि यह मौका दिया जाता है तो अवश्य ही ऐसे कई अध्यापक निकलेंगे जो उच्च कोटि का शोध करने में सक्षम रहेंगे। यह भी विश्वास जताया गया कि लक्ष्य निर्धारित होने पर महाविद्यालय भी अपने संसांधन में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहा गया कि महाविद्यालय के अध्यापकों की गुणवत्ता पर कोई भी आशंका नहीं है क्योंकि वह भी यूनिवर्सिटी से ही अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं एवं एक एंट्रेंस एग्जाम तथा इंटरव्यू पास करने के बाद ही महाविद्यालयों में कार्यरत हो पाते हैं।

कई अध्यापकों ने महाविद्यालयों के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि लैबोरेट्री का सामान या लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर या अंतरराष्ट्रीय जर्नल तक पहुंच के अभाव में छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह भी आशंका जताई कि यदि सभी महाविद्यालयों को पीएचडी कराने का अवसर दिया जाता है तो क्या इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को विवि एक साथ कोर्स वर्क करा पाएगा।

RASHTRIYA SAHARA PAGE 5

लविवि : 'कोर्स वर्क' को लेकर शिक्षकों ने जताई आशंका

लखनऊ (एसएनबी)। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध का दायरा वढ़ाने एवं नई शिक्षा नीति के शोध को वढ़ावा देने को लेकर सोमवार को एक वैठक का आयोजन किया, जिसमें यह आशंका भी सामने आई कि यदि सभी महाविद्यालयों को इतनी अधिक मात्रा में पीएचडी कराने का अक्सर दे दिया गया तो इतने अधिक छात्रों का कोर्स वर्क पूरा कराने को लेकर विश्वविद्यालय क्या व्यवस्थाएं कर पाएगा। सोमवार को राकेश चंद्रा की अध्यक्षता में हुई वैठक में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, डीआरसी के चेयरपर्सन एवं समस्त संकाय अध्यक्षों की एक वैठक डीन एकेडमिक्स प्रो. राकेश चंद्रा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर पूनम टंडन, संगीता साहू, प्रधानाचार्य, नेताजी सुभाष राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीगंज डॉ अनुराधा तिवारी और प्रधानाचार्य, डीएवी डिग्री कॉलेज ऐशवाग अंजनी मिश्रा मौजूद थे।

पांच सदस्यीय समिति ने कई आशंकाओं को लेकर किया मंथन

समिति के सदस्य-शिक्षकों ने कहा कि महाविद्यालयों को यदि यह मौका दिया जाता है तो अवश्य ही ऐसे कई अध्यापक निकलेंगे जो उच्च कोटि का शोध करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही यह भी विश्वास जताया गया कि टारगेट के सेट होने पर महाविद्यालय भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह भी कहा गया कि महाविद्यालय के अध्यापकों की गुणवत्ता पर कोई भी आशंका नहीं है क्योंकि वह भी यूनिवर्सिटी से ही अपनी शिक्षा प्राप्त करते है एवं एक एंट्रेंस एग्जाम तथा इंटरव्यू पास करने के वाद ही महाविद्यालयों में कार्यरत हो पाते है। कई अध्यापकों ने उपयुक्त उपकरण जैसे लैवोरेट्री का सामान या लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर या अंतरराष्ट्रीय जर्नल तक एक्सेस के अभाव में किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नही किया जा सकता। सभी अध्यापकों ने पक्ष रखे और डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर राकेश चंद्रा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया।

लविवि प्रवक्ता ने वताया कि ऐसी ही एक वैठक मंगलवार को भी वुलाई गई है, जिसमें डीन एकेडमिक्स और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के साथ विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य भी मौजूद होंगे और कल उनके विचार सभी के समक्ष साझा किए जाएंगे। वही दूसरी तरफ लुआक्टा अध्यक्ष डॉ मनोज पांडे ने कुलपति से मांग की है कि स्नातक स्तर पर अध्यापन करने वाले शिक्षको को शोध पर्यवेक्षक वनाने की मांग की है।

दो विषयों की पीएचडी प्रवेश मेरिट घोषित

लखनऊ। लविवि के पीएचडी प्रवेश सत्र 2019-20 के कम्प्यूटर साइंस एवं होम साइंस विषयों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांको के आधार पर कम्प्लीट मेरिट सूची आनलाइन विश्वविद्यालय की वेवसाइट के एडमिशन पेज पर जारी कर दी गयी है। अभ्यर्थी मेरिट सूची में अपना स्थान देख सकते है। 8 जून 2021 को सत्र 2019-20 के पी एच डी कम्प्यूटर साइंस एवं होम साइंस विषयों में रिक्त सीटों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची आनलाइन जारी कर दी जाएगी एवं अभ्यर्थियों को आनलाइन फ़ीस जमा करने के लिए चार कार्य दिवसों का समय दिया जाएगा।

DAINIK JAGRAN PAGE 7

पीएचडी के लिए सुधारने होंगे संसाधन

महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर शोध शुरू करने के लिए बैठक में हुई विस्तार से चर्चा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : नई शिक्षा नीति में शोध को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर शिक्षकों को शोध करने और कराने का मौका देने की तैयारी है। इसके लिए कालेजों को भी अपने संसाधन सुधारने होंगे। सोमवार को विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक्स प्रो. राकेश चंद्रा की अध्यक्षता में हुई सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, डीआरसी के चेयरपर्सन एवं समस्त संकाय अध्यक्षों की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया।

डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय के पास ऐसे कई अध्यापकों के आवेदन आए हैं, जो शोध कराना और करना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे सभी शिक्षकों के शोध करियर के भविष्य को ध्यान में रखना जरूरी है। कई शिक्षकों ने कहा कि महाविद्यालयों को यदि यह मौका दिया जाता है तो ऐसे कई अध्यापक निकलेंगे जो उच्च कोटि का शोध करने में सक्षम रहेंगे। यह भी विश्वास जताया गया कि टारगेट के सेट होने पर महाविद्यालय भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे।

वहीं, कुछ शिक्षकों ने महाविद्यालयों की कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। यह भी कहा कि यदि सभी महाविद्यालयों को पीएचडी कराने का अवसर दिया गया तो इतनी बड़ी मात्रा के छात्रों को विश्वविद्यालय एक साथ कोर्स वर्क कैसे कराएगा। बैठक में व्यापार प्रशासन विभाग से डा. संगीता साहू, नेताजी सुभाष राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीगंज की प्राचार्या डा. अनुराधा तिवारी और डीएवी डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. अंजनी मिश्रा शामिल हुए। मंगलवार को महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक बुलाई गई है।

जानकारी

- लक्ष्य पर महाविद्यालय भी करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की कोशिश
- नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के करियर में होगा सुधार

योग के फाउंडेशन कोर्स के लिए 10 तक कराएं पंजीकरण

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर केंद्रीय विवि में संस्कृत और योग को लेकर 50 घंटे का फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा। कुलपति प्रो. संजय सिंह ने बताया कि मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी और ली जा सकती है। विवि ने इंडियन योग एसोसिएशन के साथ मिलकर आनलाइन योग का फाउंडेशन कोर्स चलाने का निर्णय लिया है। विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य 10 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदक जानकारी बीबीएयू की वेबसाइट www.bbau.ac.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

शोध पर्यवेक्षक बनाने की मांग

लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ(लुआक्टा)ने स्नातक में पढ़ाने वाले शिक्षकों को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने की मांग की है। सोमवार को इस संबंध में संघ ने कुलपति को ज्ञापन भेजा। अध्यक्ष डा. मनोज पांडेय और महामंत्री अंशु केडिया ने कहा कि यूजी शिक्षकों को शोध का अधिकार देने का निर्णय सही है, लेकिन स्नातक स्तर पर छात्रों को अध्यापन करने वाले शिक्षकों को शोध पर्यवेक्षक भी बनाया जाना चाहिए।

लविवि के आनलाइन लर्निंग सिस्टम में शामिल हो सकेंगे कालेज

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कालेजों और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए दिया मौका, विद्यार्थियों की परेशानी का रखा जाएगा ध्यान

लखनऊ विश्वविद्यालय के आनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग अब कालेज और दूसरे विश्वविद्यालय भी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराना होगा। नामांकन करने वाले संस्थानों को विश्वविद्यालय प्रशिक्षण देगा, साथ ही उन्हें बैकअप भी प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय ने महामारी के शुरुआत में छात्र हित में आनलाइन शिक्षण के लिए व्यावसायिक आनलाइन प्लेटफार्म का परीक्षण किया था। प्रवक्ता डा. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित इन-हाउस कापीराइट डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रैटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फार ट्रांसफार्मेटिव एजुकेशन (स्लेट) दो से अधिक शैक्षणिक सत्रों से चल रहा है। यह छात्रों और शिक्षकों की जरूरतों के अनुरूप है। छात्र मूल्यांकन, टाइम टेबल मैनेजमेंट, छात्र उपस्थिति की निगरानी, फाइलों का आदान-प्रदान सहित तमाम सुविधाएं हैं, इसलिए कोई भी शिक्षण संस्थान इसमें मामूली शुल्क के आधार पर नामांकन कर इसका प्रयोग कर सकते है। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

एलयू: पीएचडी प्रवेश परीक्षा की मेरिट जारी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश सत्र 2019-20 के कम्प्यूटर साइंस एवं होम साइंस विषयों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर कम्प्लीट मेरिट सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर जारी कर दी गयी है। 8 जून 2021 को सत्र 2019-20 के पीएचडी कम्प्यूटर साइंस एवं होम साइंस विषयों में रिक्त सीटों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची आनलाइन जारी कर दी जाएगी एवं अभ्यर्थियों को आनलाइन फीस जमा करने के लिए 4 कार्य दिवसों का समय मिलेगा।

TOI PAGE 2

LU's hi-tech pharma institute to be completed by next year

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Students aspiring to make a career in pharmacy will soon have a dedicated government institute in the city to fulfil their dreams.

Lucknow University is set to open an Institute of Pharmaceutical Sciences (IPS) on a sprawling 8,170 square metres area on its second campus in Jankipuram.

The proposal to open the institute under the engineering faculty has received a go ahead in the university's finance committee meeting and now it will be put before the executive committee on June 11 for final approval.

The three-storeyed hi-tech building will be equipped with four advanced laboratories and gradually developed into a dedicated research institute with the setting up of modern laboratories for microbiology, pharmaceutical chemistry, central instrumentation, biotechnology, human anatomy physiology and pharmacognosy.

The construction work of the institute is likely to be over by next year, till then pharmacy classes will be run on a floor in LU's engineering faculty.

Two self-finance courses – bachelors in pharmacy (BPharma) with 100 seats and diploma in pharmacy (DPharma) with 60 seats – will be offered at the institute for which 33 contractual faculties will be appointed.

The application for two courses for academic session 2020-2021 will be invited shortly once the university receives approval from the Pharmacy Council of India.

IPS will have four departments: pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacology and pharmacognosy.

BPharma course will be of four years (eight semesters) while D Pharma will be of two years (annual pattern). M Pharma course may start after two years as per the policy of Pharmacy Council of India, New Delhi.

"The main objective of the institute is to excel in pharmacy education, engage in cutting edge research to advance healthcare and drug discovery which is the need of the hour in the times of Covid 19 pandemic. Innovative research in pharmaceutical, biomedical, and clinical sciences and practices will be focused," director, IPS, Prof Naveen Khare said.